अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शनिवार, 29 दिसंबर 2018

एक सतत विकास ढांचे में रोजगार सृजन की रणनीति शामिल होनी चाहिए...
...शरण बरो, *आईटीयूसी की पहली महिला महासचिव*

तीन तलाक जैसी कुप्रथा का समर्थन कोई भी सभ्य समाज नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार के बीच तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का रास्ता लगातार बाधित हो रहा है।

तीन तलाक की राह

तीन तलाक के खिलाफ 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018' को सरकार ने न केवल करीब एक साल बाद लोकसभा में फिर से पारित करवा लिया है, बल्कि विपक्ष की मांगों को मानते हुए किए गए कुछ संशोधन इसकी कठोरता को भी थोड़ा कम करेंगे। उदाहरण के लिए, अब पीड़िता और उसके खून के रिश्तेदार को ही प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार होगा, जबकि पहले के मसौदे में तीन तलाक के खिलाफ मुकदमा कोई भी दर्ज करा सकता था। इसी तरह अब पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को जमानत देने और समझौता कराने का अधिकार दिया गया है, जबकि पहले न केवल पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार था, बल्कि समझौते का भी कोई प्रावधान नहीं था। तीन तलाक जैसी कुप्रथा का कोई भी सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। सिर्फ यही नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय इसे असांविधानिक बता चुका है, बल्कि दुनिया के बाईस देशों में यह गैरकानूनी है। अलबत्ता मुश्किल यह है कि अपनी जिस पहल को सरकार स्वाभाविक ही मुस्लिम महिलाओं के लिए इंसानियत और इंसाफ का मामला बता रही है, उसे विपक्ष की सहमति के बगैर वह कानून का रूप नहीं दे सकती। एक साल बाद कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में पेश और पारित किए जाने के बावजूद राज्यसभा में इसके पारित होने की संभावना क्षीण ही है, क्योंकि न तो उच्च सदन में सरकार का बहुमत है और न ही विपक्ष के आरोपों की धार मंद पड़ी है। विपक्ष इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को संविधान के खिलाफ बता रहा है, साथ ही, दीवानी मामले को आपराधिक बना देने, क्योंकि इसमें पति को तीन साल जेल का प्रावधान है, पीड़िता के लिए मुआवजा तय न करने, लैंगिक समानता की अनदेखी करने और एक समुदाय विशेष को लक्षित करने के लिए भी इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने की मांग कर रहा है।

सरकार के लिए मुश्किल स्थिति इसलिए भी है कि तीन तलाक पर अन्नाद्रमुक और बीजद जैसे वे दल भी विपक्षी खेमे में हैं, जो उसके साथ होते थे। इसलिए तीन तलाक के खिलाफ लाए गए संशोधित विधेयक पर विपक्ष के तेवर को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। उल्टे यह सवाल उठेगा ही कि राज्यसभा के समीकरणों को देखते हुए सरकार इस पर अध्यादेश क्यों लाई थी, और अब फिर इसे लोकसभा से पारित कराने के पीछे का गणित क्या है।

शिक्षा और रोजगार बाजार के बीच खाई

भले ही भारत और अन्य जगहों पर शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं, लेकिन समाज के सामने सवाल यह है कि जो युवा अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब तक जिन्हें काम नहीं मिला है, उन्हें कैसे एकीकृत किया जाए।

पिछले तीस वर्षों में भारत ने अपने नागरिकों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, 1984 और 1987 में राजस्थान में शिक्षाकर्मी कार्यक्रम जैसी राज्य स्तरीय नीतियों से शुरुआत करके केंद्र में 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून तक शिक्षा को लेकर विधायी और कार्यक्रम के जरिये जबर्दस्त रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसके साथ प्राथमिक स्तर पर पहुंच और प्रावधान में वास्तविक विस्तार हुआ है। शिक्षा से संबंधित जिला सूचना प्रणाली के मुताबिक, देश में सरकारी स्कूलों की संख्या काफी बढ़ी है। केंद्रीय स्तर के पहले प्रयास 'सर्व शिक्षा अभियान' के पारित होने के सोलह वर्ष बाद क्या कुछ हुआ है? उत्साहजनक रूप से समय के साथ इसमें वास्तव में सफलता मिली है। भारत में शिक्षा तक पहुंच लगभग सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित हुई है और लड़कियों समेत पहले से कहीं ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जा रहा है।

एमेरिक डेविस

इन कार्यक्रमों ने स्कूलों का निर्माण किया है, स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है और वे लंबे समय तक स्कूलों में टिक रहे हैं। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि यह रोजगार और मजदूरी भी बढ़ा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सेन डियागो के गौरव खन्ना द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र में पाया गया है कि स्कूली शिक्षा में अतिरिक्त वर्ष की पढ़ाई का रोजगार बाजार में अच्छा लाभ मिलता है और शिक्षा के विस्तार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी व्यापक नीतियों से उच्च कुशल से निम्न-कुशल श्रमिकों की आय का विस्तार होता है। ये सभी वास्तविक उपलब्धियां हैं, जिसका जश्न मनाना चाहिए, लेकिन यहीं पर उत्साह खत्म हो जाता है।

शिक्षण के मोर्चे पर तस्वीर उतनी गुलाबी नहीं है। साल-दर-साल 'असर' (एएसईआर) की रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें दर्शाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के सीखने का स्तर कम है और संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2017 में असर ने प्राथमिक स्तर के बच्चों से ध्यान हटाकर चौदह से 18 वर्ष के बड़े बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया कि वहां क्या हो रहा है। यहां भी शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बेहतर नहीं था। इस आयु वर्ग के छात्रों में गणित और पठन क्षमता खराब थी और यह सरकार के अपने मानदंड से भी नीचे था। जबकि सरकार का अपना नेशनल एचीवमेंट सर्वे ज्यादा उत्साहजनक है। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टुडेंट एसेसमेंट (पीसा) टेस्ट, 2009 में भारत का प्रदर्शन इतना विवादास्पद था कि भारत फिर कभी पीसा में शामिल नहीं हुआ, हालांकि भारत ने 2021 में फिर से पीसा में शामिल होने का फैसला किया है। खराब शिक्षण स्तर की यह कहानी लोगों को अच्छी तरह से पता है।

इन दो विरोधाभासी निष्कर्षों का हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ शिक्षा की पहुंच बढ़ी है, यह रोजगार बाजार में वास्तविक लाभ दिखा रहा है और यह कम कुशल श्रमिकों को कुशल बना रहा है। दूसरी तरफ, छोटे और बड़े बच्चों की सीखने की क्षमता कम है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है और अन्य देशों की तुलना में यह बहुत खराब है। स्कूली प्रणाली से बाहर आने और कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के बढ़ते जनसांख्यिकीय उभार के साथ एक नई चिंता उभरने लगी है। शिक्षा व्यवस्था के वायदे गुणवत्ता के स्तर पर विफल साबित हो रहे हैं और यह उन लोगों के लिए भयानक हो सकता है, जिन्होंने दुनिया से वायदा किया है।

मेरे अपने शोध का निष्कर्ष बताता है कि जिन्होंने लंबे समय तक स्कूली शिक्षा पाई है, वे भारत के कई सार्वजनिक संस्थानों पर कम भरोसा करते हैं। मानव विकास सर्वे का इस्तेमाल करके मैंने पाया कि जिन बच्चों ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के जरिये शिक्षा पाई है, और फिर घरों में रहते हैं, वे सार्वजनिक संस्थानों पर कम भरोसा करते हैं।

सबसे चिंताजनक बात है कि डीपीईपी से शिक्षा पाने वाले आज वयस्क हैं और उनकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं और आर्थिक आकांक्षाएं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आंकड़े बताते हैं कि भले ही ये लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये श्रम बाजार के असंगठित और अल्पकालिक, संविदात्मक श्रम के क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं। जाहिर है, आकांक्षाओं और वास्तविकता के बीच की खाई ने यह नाराजगी पैदा की है।

तो भारत क्या कर सकता है? इसके दो समाधान हैं-स्कूलों को ठीक करें या स्कूल से रोजगार में प्रवेश की व्यवस्था को दुरुस्त करें। बेशक स्कूलों को ठीक करना सबसे महत्वपूर्ण है और यहां काफी कुछ किया जाना है। स्कूलों में बहुत अधिक विश्वास बनाए रखना एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि इससे उन युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जो रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनमें और अविश्वास बढ़ता है। मगर स्कूलों को अपनी विफलताओं और बाहरी दुनिया की विफलताओं, दोनों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अब बचता है, स्कूल से रोजगार तक की व्यवस्था को दुरुस्त करना। यहां अधिकांश समाधान राज्य पर निर्भर है। सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार (सरकारी नौकरी) भारत की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार नहीं बढ़े हैं। देवेश कपूर (सीएएसआई के निदेशक) के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पिछले दशक में वास्तव में घटे हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार स्पष्ट रूप से जारी है। हालांकि यह रोजगार की तलाश करने वाले सभी युवाओं को समायोजित नहीं करेगा, लेकिन यह देश के कुछ सार्वजनिक प्रबंधन मुद्दों को ठीक करने के साथ-साथ कुछ लोगों को समायोजित करने में अवश्य मदद करेगा। इसके बाद सामान्य प्रशिक्षण, रोजगार बाजार में समन्वय और युवाओं को काम पर रखने के लिए नियोक्ताओं के समर्थन की आवश्यकता है। यहां मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले देशों के लिए परिणाम उत्साहजनक हो सकते हैं।

स्पष्ट है कि युवाओं को बड़े समाज में एकीकृत करने का सवाल सार्वभौमिक है, जो भारत की तुलना में अधिक क्षेत्रों में फैला है। हालांकि समाधान शिक्षा के साथ संबद्ध नहीं है। भले ही भारत और अन्य जगहों पर शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं, लेकिन समाज के सामने सवाल यह है कि जो युवा अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब तक जिन्हें काम नहीं मिला है, उन्हें कैसे एकीकृत किया जाए।

-लेखक हार्वर्ड ग्रैजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

साइकिलिंग साहस का अद्भुत अनुभव है

अपनी कहानी

>> वेदांगी कुलकर्णी

हम सभी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो हमारी जिज्ञासा को मरने न दे। मैं खुद को धनवान मानती हूं कि मां-बाप के रूप में मेरे साथ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने मुझे फिनिश लाइन तक पहुंचने में मदद की है।

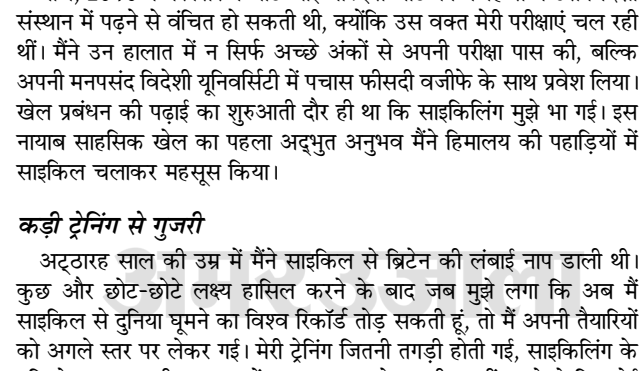

मेरा जन्म पुणे में हुआ था। मेरा झुकाव हमेशा से साहसिक कामों के प्रति रहा है। और मैं चाहती थी कि जिंदगी में कुछ ऐसा करूं, जो मुझे दुनिया से अलग दिखाए। फिर चाहे कोई अनूठी किताब लिखनी हो, अपनी खुद की फिल्म बनानी हो या फिर अपने आप को ही ब्रांड बनाना हो, मेरे दिमाग में यही सब चलता था। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का असर था कि मैं किशोरावस्था में ही कई बार अवसाद का शिकार हुई। लेकिन इसे मेरी मानसिक मजबूती ही कहेंगे कि उन्नीस साल की होते-होते मैंने साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने के बारे में सोच लिया था।

मां-बाप का साथ

मेरी सफलता के पीछे माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भारतीय समाज में अपनी उन्नीस बरस की बेटी को इतना कठिन काम करने की अनुमति देना सामान्य बात नहीं है। घर वालों की मदद से मैं ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूं। वहीं रहकर मैंने करीब दो साल पहले साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने की तैयारी शुरू की थी। यात्रा का करीब अस्सी फीसदी हिस्सा मैंने अकेले पूरा किया है। इस दौरान मैंने शून्य से 20 डिग्री कम से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना किया है।

खेल प्रबंधन की विदेशी पढ़ाई

मार्च, 2016 में मेरे सिर में चोट आई थी। इस चोट की वजह से मैं उस विदेशी संस्थान में पढ़ने से वंचित हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी परीक्षाएं चल रही थीं। मैंने उन हालात में न सिर्फ अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा पास की, बल्कि अपनी मनपसंद विदेशी यूनिवर्सिटी में पचास फीसदी वजीफे के साथ प्रवेश लिया। खेल प्रबंधन की पढ़ाई का शुरुआती दौर ही था कि साइकिलिंग मुझे भा गई। इस नायाब साहसिक खेल का पहला अद्भुत अनुभव मैंने हिमालय की पहाड़ियों में साइकिल चलाकर महसूस किया।

कड़ी ट्रेनिंग से गुजरी

अट्ठारह साल की उम्र में मैंने साइकिल से ब्रिटेन की लंबाई नाप डाली थी। कुछ और छोट-छोटे लक्ष्य हासिल करने के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं साइकिल से दुनिया घूमने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकती हूं, तो मैं अपनी तैयारियों को अगले स्तर पर लेकर गई। मेरी ट्रेनिंग जितनी तगड़ी होती गई, साइकिलिंग के प्रति मेरा जुनून उसी अनुपात में बढ़ता गया। लोग यकीन नहीं करते थे कि कोई इस उम्र की लड़की हर दिन सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चला सकती है।

चुनौतियों की कमी नहीं

मेरी साइकिल यात्रा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरी। मैंने कई चुनौतियों का सामना किया। कनाडा में एक भालू मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने कई रातें अनजान इलाकों में अकेले बिताई हैं। यही नहीं, स्पेन में तो मुझसे चाकू की नोक पर लूटपाट भी हुई। इन दिक्कतों के बावजूद मैं अपने लक्ष्य से तनिक भी नहीं घबराई। चौदह मुल्कों की करीब तीस हजार किलोमीटर सड़कों पर साइकिल चलाने के बाद सबसे तेज एशियाई के रूप में मेरी पहचान मेरी शुरुआत भर है, अंत नहीं।

-साइकिल से विश्व भ्रमण करने वाली सबसे तेज एशियाई के साक्षात्कारों पर आधारित।

सूत्र

>> फाराह ग्रे

खुद से पूछे सवालों ने बदली राह

मेरा जन्म शिकागो के एक गरीब परिवार में हुआ। हमारे रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न था। हमारे पास जीने के लिए बहुत कम साधन थे, फिर भी हमें विश्वास था कि चीजें सुधरेंगी। मुझे हमेशा अपनी उम्मीदों और सपनों पर भरोसा था। बचपन से ही मेरी मां मुझे पैसे के बारे में बताती थीं। मुझे खाना, रोशनी और देह पर कपड़ा मुहैया कराने के लिए उन्हें तीन-तीन काम करने पड़ते थे। वह चाहती थीं कि मैं पैसे का महत्व समझूं। अपनी मां की सीख की बदौलत ही मैं स्वयं से यह सवाल पूछने लगा कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं और कैसे अपने घर में योगदान कर सकता हूं। इन्हीं सवालों ने मेरी जिंदगी बदल दी।

मां की बीमारी ने मुझ पर और दबाव डाला। अंततः मैंने पत्थरों को रंगकर बेचना शुरू किया, क्योंकि मैं जानता था कि ये पत्थर पेपरवेट वगैरह का काम कर सकते हैं। गरीबी ने ही मुझे नया सोचने और करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा मैंने कई तरह के क्रीम, बेबी पाउडर आदि मिलाकर घर में ही बॉडी लोशन बनाना शुरू किया और उसे घर-घर जाकर बेचने लगा। चूंकि मैं पड़ोस के कई लोगों को जानता था, इसलिए आठ साल की उम्र में मैंने एक क्लब बनाया, जो युवाओं को कुछ सकारात्मक काम करने के लिए प्रेरित करता था। हम स्थानीय व्यवसायियों को अपनी बैठक में आमंत्रित करते और कहते कि वे हमें व्यवसाय के गुर सिखाएं। आज यही तो बिजनेस स्कूलों में सिखाया जाता है। वह क्लब बहुत सफल रहा और उससे हमारे जैसे कई लोग वास्तव में लाभान्वित हुए। फिर तो जैसे मुझे पैसे कमाने का आइडिया ही मिल गया और मैं रुका नहीं। जब मैं दस वर्ष का था, तभी मैंने एक क्लब बनाया, जिससे नींबू पानी स्टैंड के लिए पंद्रह हजार डॉलर उठाया। बारह वर्ष में मैंने वेंचर कैपिटल कंपनी बनाई, जिसने किशोर उम्र के उद्यमी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेशकों से दस लाख डॉलर जुटाए। सोलह वर्ष से पहले ही मैंने ऐसा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें प्रीपेड फोन कार्ड्स, मेल बॉक्स, कई फ्रेंचाइजी और युवाओं के लिए एफएम पर टॉक शो उपलब्ध थे। जब मुझे सफलता का स्वाद मिला, तो मैंने जीवन में मुड़कर नहीं देखा। मेरा मानना है कि उद्यमिता सबसे पहले स्कूल के लंचरूम से शुरू होती है, जब बच्चे अपनी-अपनी चीजें एक-दूसरे से बदलते हैं। जीवन विचारों, उत्पादों और सेवाओं के विनिमय तथा समस्याओं को अवसरों में बदलने के सिवा कुछ नहीं है।

जीवन विचारों, उत्पादों और सेवाओं के विनिमय तथा समस्याओं को अवसरों में बदलने के सिवा कुछ नहीं है।

फैक्ट फाइल

कतर्नियाघाट अभयारण्य

>> कतर्नियाघाट का एक दृश्य

यह बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है।

अंतरराष्ट्रीय गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा को हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच के कतर्नियाघाट संरक्षित वन क्षेत्र में शिकार करते हुए गिरफ्तार किया गया है। कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा के मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है और यह बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसमें चार रेंज हैं और पूरे वन्य विहार में छह वन रेंज हैं। इसमें दो रेंज बफर क्षेत्र के रूप जाने जाते हैं। 1987 में इसे 'प्रोजेक्ट टाइगर' के दायरे में लाया गया था। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर यह संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कतर्नियाघाट के जंगल दुधवा और किशनपुर के साथ ही नेपाल के बर्दिया के बीच बाघों की बसावटों के लिए रणनीतिक संपर्क बनाते हैं। इसके नाजुक तराई पारिस्थितिकी तंत्र में साल और सागौन के जंगल, घास के मैदान, अनेक दलदल शामिल हैं। वास्तव में यह अभयारण्य अनेक लुप्तप्राय जंतुओं का घर है, जिनमें बाघ, घड़ियाल, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन, गेंडा, हिरण, खरगोश आदि प्रमुख हैं। यहां जंगल के बीच गेरुआ नदी बहती है, जिसका उद्गम नेपाल में है। इस नदी को घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए शरण स्थल घोषित किया गया है। यहां दुर्लभ प्रजाति के कछुए, ताजा पानी में पाई जाने वाली मछलियां और अन्य कई प्रकार के जलीय प्राणी भी देखे जा सकते हैं।

कांगो में लोग सड़क पर

वहां चुनाव आयोग ने सत्ता विरोध के गढ़ तीन शहरों को मतदान से बाहर रखने की घोषणा की है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए किमिको डे फ्रेयेट्स

कांगो में चुनाव में हो रही देरी से नाराज आंदोलनकारियों ने बृहस्पतिवार को देश के पूर्वी इलाके में एक इबोला चिकित्सा केंद्र में तोड़फोड़ की और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। दरअसल कांगो में यह विरोध और हिंसा चुनाव आयोग की उस घोषणा के बाद शुरू हुई, जिसमें उसने बेनी और दूसरे पूर्वी शहर बूटेम्बो को मतदान से अलग रखने की बात कही। आयोग का कहना है कि इबोला वायरस के विस्फोटक होने के कारण इन दो शहरों को वोटिंग से बाहर रखा जाएगा। एक और शहर युम्बी के लोग भी राष्ट्रपति, संसद और प्रांतीय गवर्नरों के चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन युम्बी को इबोला के कारण नहीं, बल्कि हिंसा के कारण वोटिंग से बाहर रखने की घोषणा की गई है। चूंकि ये तीनों ही शहर सत्ता-विरोधी माहौल के लिए चर्चा में हैं, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि चुनाव आयोग का फैसला राजनीति से ही प्रेरित है। मुख्य विपक्षी गठबंधन ने इन तीन शहरों को मतदान से बाहर रखने के फैसले के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया है। गौरतलब है कि कांगो में कुल चार करोड़ मतदाता हैं, जबकि इन तीन शहरों में मतदाताओं की संख्या करीब बारह लाख है।

चुनाव में हो रही देरी कांगो जैसे देश पर भारी पड़ रही है, जहां न केवल इबोला वायरस का भीषण प्रकोप है, बल्कि कम से कम सौ हिंसक समूहों के सक्रिय होने के कारण आम नागरिकों के लिए सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव में पहले ही दो साल की देर हो चुकी है। पिछले रविवार को वहां मतदान होना था, लेकिन अचानक फिर इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया। कांगो की जनता राष्ट्रपति जोसफ कबीला के सत्तरह साल के शासन से मुक्ति चाहती है, लेकिन खुद कबीला ने इसी महीने सत्ता में लौटने की अपनी इच्छा जाहिर कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वर्ष 2001 में सत्ता संभालने के बाद कबीला ने विदेशी कंपनियों को अपने यहां निवेश के लिए बुलाकर अच्छा संकेत दिया था। लेकिन आम लोगों तक विकास का लाभ पहुंचना तो दूर, उनके कार्यकाल में तानाशाही बढ़ गई है।

इन सब के बीच चुनाव में हो रही देरी के कारण लोगों का गुस्सा फूट रहा है। स्थानीय राजनेताओं का आरोप है कि चुनाव में देरी सुनियोजित है, जिसके पीछे आबादी के उस बड़े हिस्से को मतदान से दूर रखने की साजिश है, जो दो विपक्षी नेताओं फेलिक्स सिशेड्की और मार्टिन फायुलू के समर्थक हैं। गौरतलब है कि कबीला ने इसी साल एक पूर्व मंत्री इमानुल रमाजानी शेडारी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर लोगों को चौंका दिया था। अव्वल तो इमानुल को देश के ज्यादातर लोग नहीं जानते। तिस पर जो उन्हें जानते हैं, उनको मालूम है कि पिछले साल कांगो में सत्ता-विरोधी प्रदर्शन को बेहद बर्बरता से कुचल देने के कारण यूरोपीय संघ ने इमानुल को प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में डाल दिया है। यूरोपीय संघ के इस फैसले की प्रतिक्रिया में बृहस्पतिवार को ही कबीला की सरकार ने यूरोपीय संघ के राजदूत को अपने यहां से निकाल दिया।

इस हफ्ते के शब्द

डब्ल्यू वी रमन

को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। वह रमेश पोवार का स्थान लेंगे।

एपिफेनी (EPIPHANY)

मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार यह शब्द इस वर्ष के चर्चित शब्दों में रहा। इसका मतलब अचानक से हुई अनुभूति से है।

ट्विटर पर लोकप्रिय

17 लाख

से ज्यादा लाइक मिले सात सदस्यीय कोरियाई बैंड 'बीटीएस' के वीडियो को, जो इस वर्ष ट्विटर पर सर्वाधिक है।